भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3587

उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

एनईपी 2020 के अनुरूप डिजिटल शिक्षा पहल

†3587. **प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:**

श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषरूप से महाराष्ट्र के ग्रामीण और जनजातीय जिलों में एनईपी, 2020 के अनुरूप कोई विशिष्ट डिजिटल शिक्षा पहल शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित विद्यालयों और छात्रों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में एनईपी 2020 के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा अवसंरचना को बढ़ाने के लिए एडटेक कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने पर विचार है और यदि हां, तो भागीदारों के नाम और सहयोग की प्रकृति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) क्या सरकार की एनईपी-2020 के अंतर्गत महाराष्ट्र में डिजिटल शिक्षा अवसंरचना के विस्तार अथवा उन्नयन हेतु कोई भावी योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासन के अधीन हैं।

इस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण और जनजातीय छात्रों सहित पूरे भारत में सभी छात्रों के लिए कई व्यापक डिजिटल शिक्षा पहल शुरू की गई हैं। शिक्षा मंत्रालय देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और डिजिटल पहलों को कार्यान्वित करता है। इन पहलों का उद्देश्य हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टैबलेट, लैपटॉप और प्रशिक्षण संसाधनों सहित शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में

प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल कक्षाओं और डीटीएच चैनलों को सहायता प्रदान कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्तुत राज्य की आवश्यकता के अनुसार आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के एक भाग के रूप में दिनांक 17 मई, 2020 को पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से महाराष्ट्र के ग्रामीण और जनजातीय जिलों सहित देश भर में शिक्षा हेतु बहु-मोड पहुंच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों के उपयोग, निगरानी और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहकार्यता करते हैं। पीएम ई-विद्या में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों (एबी)/भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों को आवंटित 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं, ताकि वे कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में उनकी आवश्यकता के अनुसार पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें। शिक्षा मंत्रालय की 'पीएम ई-विद्या' पहल के तहत महाराष्ट्र राज्य को पांच चैनल (एमएच पीएम ई-विद्या 113 से एमएच पीएम ई-विद्या 117) आवंटित किए गए हैं।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्र में वन नेशन, वन डिजिटल मंच है, जिसके माध्यम से सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोडित सक्रिय पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) भी उपलब्ध कराई जाती हैं। दीक्षा में भागीदार के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों ने स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.69 लाख से अधिक सामग्री तैयार की और उसमें योगदान दिया। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 564.05 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए जा चुके हैं। हितधारकों को दीक्षा पर 300 से अधिक वर्चुअल प्रयोगशालाओं तक पहुँच प्राप्त है।

महाराष्ट्र दीक्षा में भाग लेने वालों में से एक है और इसके 10.15 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जिनके शिक्षण सत्र 30.84 करोड़ से अधिक और शिक्षण मिनट 332.07 करोड़ से अधिक हैं। राज्य ने दीक्षा पर 687 डिजिटल पाठ्यपुस्तकें अपलोड की हैं और 22,662 ई-सामग्री उपलब्ध है, जिसे महाराष्ट्र के ग्रामीण और जनजातीय जिलों सहित देश के सभी छात्र प्राप्त कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय (एमओई) 'स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय पहल' (निष्ठा) नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल शिक्षा स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को कार्यान्वित कर रहा है। निष्ठा पाठ्यक्रम प्रारंभिक, माध्यमिक, एफएलएन, ईसीसीई और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए डिजाइन और संचालित किए गए हैं और एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर पेशेवर रूप से निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री का उपयोग करके ऑनलाइन पेश किए जाते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार, प्रत्येक शिक्षक

को प्रति वर्ष न्यूनतम 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) करना होगा, जो शिक्षण, डिजिटल साक्षरता और विषय-विशिष्ट विशेषज्ञता पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र के 22.73 लाख लाभार्थियों ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से निष्ठा संबंधी पाठ्यक्रम लेकर प्रमाणन प्राप्त किया।

आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी) योजना के तहत, शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय-अधिगम का वेब अध्ययन (स्वयं) पोर्टल लॉन्च किया है ताकि "कोई भी, कहीं भी, कभी भी अधिगम" के दृष्टिकोण के साथ शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराई जा सके। स्वयम पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री प्रदान करता है, जिसे एक समग्र शिक्षण अनुभव के लिए प्रमुख संस्थानों द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर अब तक 16,530 से ज़्यादा कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें 4,100 विशिष्ट कोर्स शामिल हैं। कुल नामांकन 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए हैं, जिनमें 1.62 करोड़ से ज़्यादा विशिष्ट शिक्षार्थी शामिल हैं।

केंद्रीय बजट 2025 में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत बीएसएनएल के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करने का प्रावधान शामिल है।

सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं से सुसज्जित करने के लिए दिनांक 28 मई 2025 को एक पूरक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक आयोजित की गई। पूर्व में अनुमोदित 1,56,213 आईसीटी प्रयोगशालाओं और 1,46,040 स्मार्ट कक्षाओं के अतिरिक्त, कुल 20,456 आईसीटी प्रयोगशालाओं और 29,896 स्मार्ट कक्षाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी प्रयोगशालाओं के लिए 911.13 करोड़ रुपये और स्मार्ट कक्षाओं के लिए 630.38 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुमोदन शामिल है। महाराष्ट्र राज्य को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 839 आईसीटी प्रयोगशालाओं और 851 स्मार्ट कक्षाओं हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य ने सूचित किया है कि वे एडटेक कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों जैसे पाई जैम फाउंडेशन (ऑनलाइन स्व-मूल्यांकन के माध्यम से स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आश्वासन फ्रेमवर्क (एसक्यूएएएफ) के लिए), यूनिसेफ - यूनीलर्न प्लेटफॉर्म (मिश्रित-मोड प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा प्रमाणपत्र के लिए), खान अकादमी (कक्षा 1 से 10 के लिए डॉ. जयंत नार्लीकर गणित और विज्ञान शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम को लागू करने के लिए) और वॉवेल्स ऑफ द पीपल एसोसिएशन-वीओपीए (निपुण महाराष्ट्र पहल के हिस्से के रूप में) के साथ एनईपी 2020 के तहत डिजिटल शिक्षा अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सहकार्यता कर रहे हैं।

*****